छोटी इकाइयों को तकनीक से लैस करने पर जोर

लखनऊ। एमएसएमई इकाइयों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने को लेकर राहत दी गई है। अपनी इकाई को सूचना प्रौद्योगिकी से अपग्रेड करने के लिए दो से पांच लाख रुपये तक का अनुदान पालिसी में है। वहीं अपने कर्मचारियों को हाईटेक और आईटी फ्रेंडली बनाने के लिए 50 हजार रुपये प्रति कर्मचारी मिलेगा। कम से कम 20 लाख इकाइयां अगले एक साल में अपग्रेड हो जाएंगी।

प्रदेश के प्रत्येक एमएसएमई क्लस्टर को एक तकनीकी और एक प्रबंधन संस्थान से जोड़ा जाएगा जो क्लस्टर को अपनी सलाह देगा। ये संस्थान क्लस्टर से जुड़े मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे, जिसके लिए राज्य सरकार

प्रत्येक एमएसएमई क्लस्टर को एक तकनीकी और एक प्रबंधन संस्थान से जोड़ा जाएगा

अनुदान की व्यवस्था करेगी। तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों का चयन क्लस्टर से दूरी और गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। एससी-एसटी और पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिजायन, पैकेजिंग और मार्केटिंग में युवाओं को बाजार और मांग के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा।डिजायनिंग में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजायन लखनऊ को जोड़ा जाएगा। ऐसे एमएसएमई उत्पाद, जिनकी गुणवत्ता मानक अभी निर्धारित नहीं हैं, उनके लिए भारतीय मानक ब्यूरो और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की मदद ली जाएगी। ये संस्थान मानक तैयार करेंगे ताकि एमएसएमई उत्पादों की क्वालिटी विश्वस्तरीय बनाई जा सके। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पेटेंट और जीआई टैग पर आने वाले खर्च का अधिकतम 75 फीसदी सरकार देगी।

ये राशि अधिकतम दस लाख रुपये होगी। इसके अतिरिक्त अटार्नी शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में 50 हजार से दो लाख तक प्रदेश सरकार देगी। प्रदेश के पॉलीटेक्निक, आईटीआई और इंजीनियरिंग संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेंटरों की स्थापना की जाएगी ताकि इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक तकनीकी रूप से दक्ष युवा तैयार किए जा सकें। ब्यूरो